



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 686]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 4, 2005/आषाढ़ 13, 1927

No. 686]

NEW DELHI, MONDAY, JULY 4, 2005/ASADHA 13, 1927

पर्यावरण और वन मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 4 जुलाई, 2005

का.आ. 943(अ).—पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) के खण्ड (घ) के अधीन, उन क्रियाकलापों के सिवाय, जिन्हें पर्यावरणीय समाघातों की जांच करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुज्ञात किया जाता है, दून घाटी उत्तरांचल में विभिन्न क्रियाकलापों पर निर्बंधन अभिव्यक्ति करने वाली अधिसूचना का.आ. 102(अ) तारीख 1 फरवरी, 1989 द्वारा जारी की गई थी;

और उक्त अधिसूचना ने उद्योगों को तीन प्रवर्गों में वर्गीकृत किया है, अर्थात्, हरा, नारंगी और लाल और दून घाटी क्षेत्र में औद्योगिक इकाइयों को अनुज्ञा देने और उनको निर्बंधित करने के लिए मार्गदर्शी सिद्धांतों को भी विहित किया है;

और नारंगी प्रवर्ग के अंतर्गत आने वाले उद्योगों को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारण किए जाने की और उन्हें "अनापत्ति प्रमाणपत्र" प्रदान करने से पूर्व पर्यावरण और वन मंत्रालय में केन्द्रीय सरकार को विनिर्दिष्ट किए जाने की अपेक्षा की जाती है;

और अब यह सुनिश्चित किया गया है कि उक्त अधिसूचना में यथा-विनिर्दिष्ट नारंगी प्रवर्ग के अधीन आने वाले प्रस्तावों पर का.आ. 60(अ) तारीख 27 जनवरी, 1994 द्वारा जारी पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय निकासी की अपेक्षा करने वाले उद्योगों के रूप में कार्रवाई की जाएगी।

अतः अब पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश दिया जाता है कि अधिसूचना संख्यांक का.आ. 102(अ) तारीख 1 फरवरी, 1989 द्वारा प्रवर्गीकृत नारंगी उद्योग के प्रवर्ग के अंतर्गत आने वाले दून घाटी, उत्तरांचल के विकास संबंधित प्रस्ताव वैसी प्रक्रिया का पालन करेंगे जैसी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से समय-समय पर यथा-संशोधित का.आ. 60(अ) तारीख 27 जनवरी, 1994 द्वारा जारी पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 1994 के अधीन उद्योग सेक्टर परियोजनाओं के पर्यावरण निकासी के लिए पालन किया जा रहा है।

[फा. सं. जे-11013/25/2005-आई.ए. II(I)]

आर. चन्द्रमोहन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

ORDER

New Delhi, the 4th July, 2005

S.O. 943(E).—Whereas a notification under clause (d) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, imposing restrictions on various activities in Doon Valley Uttranchal, except those activities which are permitted by the Central Government for examining the environmental impacts, was issued vide No. S.O. 102(E) dated the 1st February, 1989;

And whereas the said notification classified industries into three categories; namely, green, orange and red and also prescribed guidelines for permitting and restricting industrial units in Doon Valley Area;

And whereas industries falling in the orange category are required to be assessed by State Pollution Control Board and referred to the Central Government in the Ministry of Environment and Forests before granting 'No Objection Certificate';

And whereas it has now been decided that proposals covered under the orange category, as specified in the said notification shall be dealt with as industries requiring environmental clearance as per the Environment Impact Assessment Notification, 1994, issued *vide* No. S.O. 60(E) dated the 27th January, 1994.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 5 of the Environment (Protection) Act, 1986, it is hereby directed that all proposals, relating to development in Doon Valley, Uttaranchal falling in the category of orange industry categorized *vide* notification No. S.O. 102(E) dated the 1st February, 1989, shall follow the same procedure as is being followed for the environment clearance of Industry Sector Projects under Environment Impact Assessment Notification, 1994 issued *vide* No. S.O. 60(E) dated the 27th January, 1994 as amended from time to time with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[F. No. J-11013/25/2005-IA.II(I)]
R. CHANDRAMOHAN, Jt. Secy.